

प्रेषक,

सुशांत पटनायक  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 04 अप्रैल, 2011

विषय:- अनुदान सं0-27 के जिला सैक्टर आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु स्वीकृत लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-209/XXVII(1)/11 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-449/215-रा0यो0आ0वा0जि0यो0/2011-12 तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-नि.1531/3-4 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अंतर्गत संचालित जिला सैक्टर योजनाओं हेतु संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार ₹ 9,60,00,000/- (रु0 नौ करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.
- (2) उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनार्थ एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
- (3) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किशतों में किया जाय.
- (4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
- (5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
- (6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

- (7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय
- (8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-०६/ख-२-२०१०-१२(११)/२००९ दिनांक ३१ मार्च, २०१० द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
- (९) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
- (१०) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- (११) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
- (१२) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-२११(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
- (१३) आयोजनागत पक्ष की चालू योजनाएँ जिन्हें पाँच वर्ष या अधिक हो गया है, का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से नियोजन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा तथा फलस्वरूप उन योजनाओं के सम्बन्ध में नियोजन एवं वित्त विभाग के परामर्श से अग्रोत्तर निर्णय लिया जायेगा.
- (१४) आयोजनागत पक्ष की प्रत्येक योजना का नियमित आधार पर अनुश्रवण/समीक्षा उनके आउटपुट एवं आउटकम लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जायेगा और यदि वांछित आउटकम/आउटपुट की उपलब्धि नहीं होती/पाई जाती है तो उनके सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जायेगा.
- (१५) जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृतियाँ पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं जिनमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है, साथ ही जिला योजनान्तर्गत ऐसी योजनाओं/कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी नहीं की जायेगी जिसमें वेतन आदि अथवा अन्य आवर्तक व्यय सम्मिलित हो।
- (१६) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के भी अधीन है कि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से शासनादेश संख्या ४४९/२१५-रा०यो०आ०/वा०जि०यो०/२०११-१२ दिनांक ०६ अप्रैल, २०११ के द्वारा निर्धारित किये गये भौतिक लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

२. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०११-१२ के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं०-२७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक २४०६-वैनिकी तथा वन्य जीवन ०१-वैनिकी ८००-अन्य व्यय ९१-जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)		
क्र.सं.	योजना का नाम / मानक मद	वर्तमान स्वीकृति
	<b>९१०१-वन संचार साधन</b>	
	२५- लघु निर्माण कार्य	३००००
	२९- अनुरक्षण	२००००
	<b>- • योग</b>	<b>५००००</b>
	<b>९१०२-भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था</b>	
	२४- वृहद निर्माण	२५०००
	२५- लघु निर्माण कार्य	८०००
	२६- मशीन साज सज्जा	३०००
	२९- अनुरक्षण	१००००
	<b>योग</b>	<b>४६०००</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>९६०००</b>

(वर्तमान स्वीकृति ₹ नौ करोड़ साठ लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग (अनुभाग-1) के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुशांत पटनायक)

अपर सचिव

संख्या-1082(1)/X-2-2011, तददिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)

अपर सचिव

शासनादेश सं०-१०८२/X-2-2011-12(28)/2006, दिनांक ०४-अप्रैल, 2011 का संलग्नक:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम								
		वन संचार साधन			भवन निर्माण एवं बिजली पानी की व्यवस्था					
		मानक मद			मानक मद					
		लघु निर्माण कार्य	अनुरक्षण	योग	वृहत निर्माण कार्य	लघु निर्माण कार्य	मशीन सज्जा/संयंत्र	अनुरक्षण	योग	कुल योग
1	नैनीताल	540	460	1000	449	143	53	355	1000	2000
2	ऊधमसिंह नगर	162	138	300	672	215	81	269	1237	1537
3	अल्मोड़ा	1150	767	1917	1913	612	230	765	3520	5437
4	बागेश्वर	1726	1150	2876	1928	617	231	771	3547	6423
5	पिथौरागढ़	810	540	1350	2464	789	296	986	4535	5885
6	चम्पावत	1944	1296	3240	2016	645	242	806	3709	6949
7	देहरादून	3780	2520	6300	3012	964	361	1205	5542	11842
8	टिहरी	3126	2084	5210	784	251	94	314	1443	6653
9	पौड़ी गढ़वाल	3820	2547	6367	4480	1434	538	1616	8068	14435
10	चमोली	2208	1472	3680	2800	896	336	1120	5152	8832
11	रूद्रप्रयाग	3156	2104	5260	965	309	116	386	1776	7036
12	उत्तरकाशी	7389	4761	12150	2688	860	323	1075	4946	17096
13	हरिद्वार	189	161	350	829	265	99	332	1525	1875
		30000	20000	50000	25000	8000	3000	10000	46000	96000

(सुशांत पटनायक)  
अपर सचिव